सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 12 आषाढ़ 1936 (श0) / 3 जुलाई, 2014 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 54

(1) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	15
(2) नगर विकास विभाग	..	..	15
(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	06
(4) कृषि विभाग	..	..	02
(5) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	..	..	07
(6) खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	..	..	06
(7) सहकारिता विभाग	..	..	03
		कुल योग ---	54

पानी मुहैया कराना

*159. श्री नितिन नवीन—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पटना में वार्ड नं० 17, चाँदपुर बेला मोड़ स्थित मोटर पम्प से गंदे व बदबुदार पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे आम जन पानी को मजबूर हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में आम नागरिकों के हित में कबतक शुद्ध पानी मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*160. डॉ० रामानन्द यादव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम वार्ड नं० 44 में एन०एच० 30 से खेमनीचक होते हुये मंगल चौक तक पथ बना हुआ है लेकिन नाला निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण हमेशा गंदे जल का जमाव रहता है और बरसात के दिनों में नारकीय स्थिति हो जाती है जिससे वहाँ के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, तो क्या सरकार उक्त पथ में नाला निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*161. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में राज्य में सुखाड़, फैलिन चक्रवात के कारण बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की क्षति हुई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा 31 जिलों में रब्बी फसल की क्षतिपूर्ति का आकलन कर मौसम आधारित फसल बीमा अंतर्गत 31 जिलों में कुल 14,13,827 किसानों को 550.88 करोड़ की राशि को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई, जबकि बीमा कंपनियों को प्रीमियम की 12,469 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी;

(3) क्या यह बात सही है कि आई०सी०आई० सी०आई०, लोम्बार्ड और एच०डी०एफ०सी०, इर्गो बीमा कंपनियों द्वारा वर्ष 2013 में रब्बी फसल का 100.74 करोड़ एवं 58.75 करोड़ रुपये का कम आकलन कर प्रीमियम की राशि 11,918.12 करोड़ राशि का गबन कर लिया गया है;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बीमा कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर आँशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि यह मामला रब्बी फसल का नहीं है, बल्कि खरीफ 2013 मौसम का है। पुनः बीमा कंपनियों को प्रीमियम की राशि 12,469 करोड़ नहीं दी गयी है बल्कि 124.69 करोड़ रुपये दी गयी है।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि आई०सी०आई० सी०आई०, लोम्बार्ड तथा एच०डी०एफ०सी०, इर्गो बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम राशि का गबन नहीं किया गया है। प्रीमियम राशि बीमा कंपनियों को सेवा शुल्क के रूप में दिया जाता है तथा संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनी को वहन करना पड़ता है। खरीफ 2013 मौसम में बीमा कंपनियों ने अपने स्वचालित मौसम केन्द्रों के मौसम आंकड़ों पर जो क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन किया वह राज्य सरकार के मौसम आंकड़ों के आधार पर आंकलित राशि से क्रमशः 100.74 करोड़ एवं 58.75 करोड़ रु० कम है।

(4) उक्त आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उक्त राशि की वसूली हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना के परामर्श के आलोक में जिला पदाधिकारी, पटना के न्यायालय में सर्टिफिकेट केस दायर किया जा चुका है। पुनः विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य के अनुसार उक्त कंपनियों को खरीफ 2013 मौसम के आँकड़ों के सत्यापन/समाधान हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

जमीन का अधिग्रहण

*162. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के लदौरा गाँव में एक सौ पचास महादलित को बसने हेतु अभीतक सरकार द्वारा जमीन मुहैया नहीं कराया गया है;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त महादलित परिवार को बसाने हेतु जमीन कबतक अधिग्रहण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*163. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के मारवाड़ी धर्मशाला चौक से एलसीटी घाट तक जाने वाली सड़क बिल्कुल खराब स्थिति में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय स्थापित करवाना

*164. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावां प्रखण्ड के ग्राम पंचायत, कोनन्दपुर में पशु चिकित्सालय नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाने हेतु कोनन्दपुर पंचायत के ग्राम बढ़ौना में 1.5 एकड़ बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-बढ़ौना में पशु चिकित्सालय स्थापित करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना का संचालन कराना

*165. श्री सबा जफर—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा चलित बोरिंग एवं पम्प योजना शुरू किया था, जिसमें पूर्णियाँ जिला के वायसी एवं धनदाहा प्रखंड को ही चयनित किया गया था, यदि हाँ, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अमौर एवं बैसा प्रखंड में उक्त योजना को संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*166. श्री संजय सिंह (टाईगर)—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 23 मार्च, 2014 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''जानवरों के 50 एम्बुलेंस को हरी झंडी का इन्तजार'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के चलन्त पशु चिकित्सालयों को प्रभावी बनाने के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 में 50 एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय लिया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि 4 करोड़ रुपया खर्च कर एक वर्ष पहले खरीदी गई यह गाड़ियाँ अबतक जिलों के बजाय ऑफिस में ही खड़ी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन गाड़ियों को गाँवों में भेजने के साथ-साथ विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*167. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट प्रखण्डान्तर्गत ग्राम-गोड़ारी का जलमीनार माह दिसम्बर, 2012 से बन्द हो जाने से जलापूर्ति पूर्णतः ठप है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार से जलापूर्ति कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान खरीदने का औचित्य

*168. डॉ० अच्युतानन्द—दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 7 मई, 2013 के अंक में छपी खबर ''लक्ष्य से आधे-धान की हुई खरीद'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य में 11 लाख 13 हजार 835.59 मेट्रिक टन ही धान की खरीद हुई जबकि लक्ष्य 30 लाख मेट्रिक टन की खरीद का था;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो लक्ष्य का मात्र 46.41 प्रतिशत ही धान खरीदने का क्या औचित्य है ?

जलमीनार बनाना

*169. डॉ० रामानन्द यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा प्रखंड के ग्राम-मोजीपुर हाट से ग्राम-मैजीपुर रेडियो स्टेशन तक की जनसंख्या लगभग 10 हजार है जबकि 5 हजार की जनसंख्या पर एक जलमीनार (पानी टंकी) निर्माण कराने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि शुद्ध पेय जलापूर्ति के अभाव में उक्त स्थानों के आम लोगों को गंगा जल पीना पड़ता है और गंगा जल में आर्सेनिक पाई जाती है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पर रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव में जलमीनार (पानी टंकी) बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*170. श्री गजानन्द शाही—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के शेखपुरा प्रखण्ड के ग्राम कोरे में पेय जलापूर्ति के लिए नलकूप तथा पाइप लाइन दो वर्ष पूर्व कार्य शुरू हुआ और अधूरा कार्य कर छोड़ दिया गया;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नलकूप तथा पाइप लाइन को पूरा कार्य करा कर जलापूर्ति करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*171. श्री जवाहर प्रसाद—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम विधान-सभा के सासाराम नगर एवं तिलौथू प्रखंड में नये राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि नये राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तय माप दण्ड के अनुसार बनाये जा रहे हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि नये राशन कार्ड के सर्वे में भारी अनियमितता हुई, जिसके कारण वैसे उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा से वंचित हो गये जो उसके हकदार थे;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर उचित कार्रवाई करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वित नहीं करने का औचित्य

*172. श्री संजय सिंह (टाईगर)—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र प्रभात खबर के दिनांक 20 फरवरी, 2014 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''बकरी चबा गयी सरकार की योजना'' के आलोक में क्या मंत्री, पशु मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में गरीबों के बीच उन्नत नस्ल की कुल बारह लाख बकरी बांटने का निर्णय लिया गया था, जो अभीतक कार्यान्वित नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

जलमीनार का निर्माण

*173. श्री विनय कुमार सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत के आम जनता को पीने के शुद्ध जल हेतु जलमीनार (पानी टंकी) का निर्माण नहीं किया जा सका है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर पंचायत, दिघवारा के लोगों को पीने के लिये शुद्ध जल हेतु जलमीनार बनवाने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

क्षतिग्रस्त पाइप लाइन बदलना

*174. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड के पी०एच०ई०डी० कार्यालय का जलमीनार वर्ष 1984 में बना जिसका पाइप लाइन अब क्षतिग्रस्त हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार के पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण आमजन अशुद्ध पेयजल पीने को विवश है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को बदलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सीवरेज एवं ड्रेनेज का निर्माण

*175. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद्ध क्षेत्र में सीवरेज व ड्रेनेज नहीं रहने के कारण गंदगी एवं डिस्चार्ज वाटर का बहाव नहीं होता है, जिसके कारण प्रतिकूल प्रभाव शहर में निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर परिषद् क्षेत्र में इसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत सीवरेज एवं ड्रेनेज का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*176. श्री कृष्णनन्दन पासवान--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत तुरकौलिया अंचल में गाँधी घाट स्थित राजस्व कचहरी भवन जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कचहरी भवन का डी०पी०आर० तैयार है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कचहरी भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दखल-कब्जा दिलाना

*177. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''भूमिहीनों ने सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड के इनरवा पंचायत के मनियरवा गाँव के वार्ड नं० 3 के भूमिहीन दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के करीब एक सौ से अधिक परिवारों को वासगीत पर्चा मिला हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन भूमिहीन पर्चाधारी परिवारों को भूमि से बेदखल होकर रेलवे स्टेशन से संतु महतो चौक सुक्की की ओर जाने वाली सड़क किनारे बसने पर मजबूर हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वासगीत पर्चाधारी भूमिहीन परिवारों को जमीन पर कबतक दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सब्सिडी दिलाना

*178. श्री रामायण मांझी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार बिहार के किसानों को वर्मी कम्पोस्ट बनाने पर सब्सिडी देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत 2012-13 का सब्सिडी किसानों को नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीवान जिला के किसानों को 2012-13 का वर्मी कम्पोस्ट सब्सिडी दिलाना चाहती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*179. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''सस्ती गैस के नाम पर करोड़ों की ठगी'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में आदित्य फ्यूल्स लिमिटेड नामक कम्पनी ने जिले में पाँच गैस एजेंसी के मार्फत 20 हजार उपभोक्ताओं से सात करोड़ की राशि वर्ष 2010-11 में वसूल किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपभोक्ताओं को मार्च, 2013 के बाद गैस आपूर्ति बंद कर दिया गया तथा कार्यालय पर भी ताला लगा दिया है एवं उपभोक्ता की राशि भी वापस नहीं किया जिससे उपभोक्ता को गैस आपूर्ति नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई कर उपभोक्ताओं की जमा राशि लौटने हेतु कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समाधान करना

*180. डॉ० (मो०) जावेद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज नगर परिषद् अन्तर्गत पश्चिम पाली चौक के निकट राजबाड़ी हौंडा शो रूम एवं जे०डी० हीरो शो रूम दोनों रोड के निकट होने के कारण सड़क से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके कारण आवागमन में लोगों को काफी परेशानी होती है और सड़क हादसे भी होते रहते हैं, क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फसल मुआवजे का भुगतान

*181. श्री विक्रम कुँवर--दिनांक 4 फरवरी, 2014 को हिन्दी दैनिक समचार-पत्र में प्रकाशित ''जिले के सैकड़ों किसान गये दूसरे राज्य कमाने'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 में फसल बर्बाद होने पर सरकारी योजना के तहत किसानों ने फसल बीमा कराया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के तीन हजार किसानों को फसल मुआवजे का लाभ नहीं मिला है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तीन हजार किसानों को फसल मुआवजे का भुगतान कबतक करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि फसल बर्बाद होने पर सरकारी योजना के तहत् किसानों द्वारा फसल बीमा नहीं कराया जाता है, बल्कि फसल बुआई के समय ही किसानों द्वारा फसल बीमा कराया जाता है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थित यह है कि खरीफ 2009 मौसम में सीवान जिले के पैक्सों द्वारा गैर ऋणी कृषकों के किये बीमा संबंधी कृषकवार सत्यापन हेतु विभागीय पत्रांक 1476, दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया । उल्लेखनीय है कि सीवान जिले में खरीफ 2009 मौसम में कुल 26,451 गैर-ऋणी किसानों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) के तहत् बीमा कराया गया था । इसमें से टास्क फोर्स द्वारा जाँचोपरान्त 23,592 गैर-ऋणी कृषकों को योग्य पाया गया तथा मात्र 2,859 गैर-ऋणी कृषक ही योग्य नहीं पाये गये । टास्क फोर्स द्वारा जाँचोपरान्त योग्य पाये गये सभी गैर-ऋणी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति राशि को विभाग द्वारा विमुक्त कर दिया गया है तथा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त राशि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान भी कर दी गयी है । शेष 2,859 कृषकों को योग्य नहीं पाये जाने के कारण उन्हें बीमा लाभ देय ही नहीं है ।

(3) उपरोक्त के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अनुकम्पा के आधार पर नौकरी

*182. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के सिटी अंचल कार्यालय में पदस्थापित सफाई पर्यवेक्षक की मृत्यु दिनांक 8 अप्रील, 2013 को सेवाकाल में हो गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उनके आश्रित को आजतक अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं दी गई है, जिससे उक्त परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खण्ड (1) में वर्णित सफाई पर्यवेक्षक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पोस्टमार्टम की व्यवस्था

*183. श्री राहुल कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना, भोजपुर सहित दस जिलों में राष्ट्रीय पशु बीमा कार्यक्रम 2010-11 से लागू है;

(2) क्या यह बात सही है कि पशुओं की मौत होने पर बीमा की राशि का भुगतान पशुपालकों को पशुओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान किया जाता है;

(3) क्या यह बात सही है कि पशुओं के पोस्टमार्टम की व्यवस्था मात्र वेटनरी कॉलेज, पटना में ही उपलब्ध होने के कारण अन्य जिलों के पशुपालकों को बीमा की राशि भुगतान नहीं हो पा रहा है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी पशु चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*184. श्रीमती पूनम देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर को यातायात को सुचारू बनाने तथा शहर को जाम से निजात पाने के लिये कुल 51 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की जानी है, जिसके लिये निगम बोर्ड तथा सशक्त स्थाई समिति द्वारा नवम्बर, 2013 में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु संचिका विभाग के पास अभीतक लम्बित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर शहर को जाम से निजात पाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*185. श्री राजेश सिंह --क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत पिपरासी प्रखण्ड के मंझरिया पंचायत के बैरी स्थान के गाँव में जलमीनार नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव में जलमीनार का निर्माण कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार बनवाना

*186. श्री राजेश सिंह --क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबनी प्रखण्ड के दमकुँआ बाजार एवं मधुबनी रंगरेली गाँव में जलमीनार नहीं होने के कारण शुद्ध जलापूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँवों में जलमीनार बनवाने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कचरा हटाना

*187. श्री नितिन नवीन : स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''पटना पर मंडरा रहा ई वेस्ट का खतरा'' को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पाँच शहरों में पहली बार हुआ ई-वेस्ट के सर्वे में बिहार राज्य प्रदुषण पर्षद के रिपोर्ट का खुलासा करते हुये कहा है कि पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में बेकार पड़े इलेक्ट्रोनिक कचरे भरे पड़े हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि इन बेकार पड़े ई-वेस्ट को अगर डिस्पोज नहीं किया गया जायेगा तो 2020 में इसकी चार गुणा अधिक बढ़ जाने की यानी 93578 मी० टन कचरा बढ़ जायेगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ई-वेस्ट कचरे को कबतक हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*188. श्री जनक सिंह : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के पानापुर प्रखण्ड में एक वर्ष से प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का पद रिक्त है, जिससे कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रिक्त पद पर कबतक प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का जीर्णोद्धार

*189. मो० आफाक आलम : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के कसबा नगर पंचायत के रानी सती चौक से बाजार होते हुये रेलवे स्टेशन का सड़क विगत 20 वर्षों से जर्जर है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु उपचार केन्द्र की स्थापना

*190. श्री शालिग्राम यादव : क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत साहर घाट मधवापुर प्रखण्ड का मध्य भाग पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि पशुपालकों की सुविधा के लिये साहर घाट में पशु उपचार केन्द्र की स्थापना अतिआवश्यक है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पशुपालकों की सुविधा के लिये पशु उपचार केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

मालगुजारी रसीद उपलब्ध कराना

*191. श्री राजेश्वर राज--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला सहित पूरे राज्य में माह नवम्बर, 2012 से मालगुजारी रसीद समाप्त है, जिससे राजस्व संग्रह प्रभावित हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने पत्रांक 232, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को विभागीय सचिव से अनुरोध किये जाने के बावजूद अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे राज्य में पर्याप्त मात्रा में मालगुजारी रसीद उपलब्ध करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*192. मो0 आफाक आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के कसबा नगर पंचायत के चाँदनी चौक से नेहरू चौक होते हुये महावीर चौक कोसी घाट तक नाला नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर नाला नहीं रहने के कारण घर का पानी सड़क पर जमा हो जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है; कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाभ पहुँचाना

*193. श्री शालिग्राम यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी एवं मधवापुर प्रखंड के पश्चिमी भाग में पशुपालकों को दूध शामिल शीतगृह नहीं रहने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखण्डों के पश्चिमी भाग के किसानों के हित में बानपुरा में कृषि विज्ञान केन्द्र में शीतगृह का निर्माण कराकर किसानों को लाभ पहुँचाना चाहती है, हाँ, तो कबतक ?

प्राक्कलन तैयार करना

*194. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखण्ड के तिलकताजपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य का प्राक्कलन तैयार करने के लिये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक 363, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को पत्र लिखा गया, फिर भी आजतक प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तिलकताजपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का प्राक्कलन तैयार नहीं करने का क्या औचित्य है ?

मुक्ति धाम का निर्माण

*195. श्री विनय कुमार सिंह-क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर एवं दियवारा के पिपरा घाट पर मुक्ति धाम के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2010-11 में दी गई जो आजतक निर्माणाधीन है, यदि हाँ, तो कुल दोनों प्रखण्ड के मुक्ति धाम का निर्माण पूर्ण कर चालू कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*196. श्रीमती भागीरथी देवी-स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 जून, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''भवानीपुर की समस्या से जूझ रहे हैं भवानीपुर ग्रामीण'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिला के गौनाहा प्रखण्डान्तर्गत ग्राम एकवा एवं भवानीपुर आदि पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ गर्मी के मौसम में भू-गर्भ का जल स्तर काफी नीचे चले जाने से सभी चापाकल एवं कुएँ सूख गये हैं, जिससे पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर जलमीनार का निर्माण कराकर ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर भवन बनाना

*197. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत नगर पंचायत, वारिसलीगंज में नगर भवन नहीं है, जिससे नगरवासियों को किसी भी प्रकार का सभा या कार्यक्रम करने में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार वारिसलीगंज नगर पंचायत में नगर भवन बनवाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

*198. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किसनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के विशनपुर बाजार में विगत् दस वर्ष पूर्व ग्रामीण जलापूर्ति योजनान्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर पम्प का निर्माण किया गया था, लेकिन अभीतक उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों को उक्त पम्प से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं की गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पम्प से उक्त क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*199. श्री गजानन्द शाही--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के शेखोपुर प्रखंड के निमि ग्राम में 4 वर्ष पूर्व पानी टंकी बनकर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पानी टंकी बनकर तैयार होने के बावजूद आजतक निमि ग्राम में जलापूर्ति नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पानी टंकी को चालू कर जलापूर्ति करने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

क्रियान्वयन कराना

*200. श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 201, दिनांक 7 सितम्बर, 2013 द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली नगर पंचायत से जलापूर्ति योजनाओं की सूचना मांगी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली के पत्रांक 345-1, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 द्वारा जलापूर्ति योजनाओं की सूची सचिव, नगर विकास विभाग को भेज दी गई थी;

(3) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राक्कलित राशि आठ करोड़ चौरासी लाख पचासी हजार का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नगर पंचायत, निर्मली के जलापूर्ति योजनाओं की क्रियान्वयन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*201. श्री जवाहर प्रसाद--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर के मुहल्ला मदार दरवाजा में जलापूर्ति पाइप लाइन नहीं जोड़ने के कारण नगर के मुहल्ला नवरतन बाजार, महाजन टोली, काजीपुरा, शहजुमा इत्यादि मुहल्ले के लोगों को जलापूर्ति बाधित है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रोहतास जिला के मदार दरवाजा में जलापूर्ति पाइप लाइन जोड़वाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*202. श्री कृष्णनन्दन पासवान--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया एवं हरसिद्धि प्रखंडान्तर्गत व्यापार मंडल का अपना भवन नहीं है, जिस कारण सहकारिता के कार्यों में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो व्यापार मंडल के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल की आपूर्ति

*203. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंडान्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत का आर्सेनिक एवं लौहयुक्त पानी है और इसके पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि मनिहारी नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार गंगा नदी का उपचारित जल आपूर्ति करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सक की पदस्थापना

*204. श्री आनन्दी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के हलधरा हाट में पशु चिकित्सालय बनकर तैयार है, किन्तु चिकित्सक के अभाव में इसमें चिकित्सा नहीं हो रही है तथा पशुधन विकास कार्यक्रम भी अवरुद्ध है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वहाँ चिकित्सक की पदस्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम का निर्माण

*205. श्रीमती पूनम देवी यादव--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 जून, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''आठ जिलों में नहीं है एक भी गोदाम'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में फिलहाल तीन लाख बाईस हजार मीट्रीक टन अनाज की प्रतिमाह जरूरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि एफ०सी०आई० का राज्य के आठ जिले खगड़िया, शिवहर, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, बांका, कैमूर तथा गोपालगंज में जिला स्तरीय गोदाम नहीं होने के कारण पी०डी०एस० दुकानों को समय पर अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खगड़िया सहित राज्य के अन्य 8 जिलों में जिला स्तरीय गोदाम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*206. श्री गिरधारी यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका में केन्द्रीय विद्यालय खुले हुए सात साल से अधिक हो गये, परन्तु जमीन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार केन्द्रीय विद्यालय, बांका को कबतक जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*207. डॉ0 इजहार अहमद——क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि——

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला स्थित डी0एम0सी0एच0 शिशु रोग वार्ड के निर्माणाधीन नीकू भवन आजतक तैयार नहीं हो पाया है, जबकि वर्ष 2012–13 में इसे पूरा किया जाना था ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसके लिये संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये जनहित में कबतक कार्य पूरा करने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*208. श्री विक्रम कुँवर——दिनांक 18 अगस्त, 2013 को हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित "फर्जीवाड़ा से उठाया 50 लाख का अनाज" के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि अगस्त, 2011 से जुलाई, 2013 के बीच सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के बीस डीलरों ने बैंक के फर्जी पे स्लिप पर राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 50 लाख से अधिक बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के अनाज का उठाव कर लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतने बड़े फर्जीवाड़ा से अनाज का उठाव करने वाले दोषी डीलरों एवं कर्मचारियों को नामजद अभियुक्त बनाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है ?

दोषी को चिन्हित करना

*209. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी——दिनांक 5 जनवरी, 2014 को स्थानीय समाचार–पत्र "दैनिक जागरण" में प्रकाशित शीर्षक "85 करोड़ हो गये 14 करोड़" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर में निगम से पंजीकृत कुल 68 विज्ञापन एजेंसियों में से 50 एजेंसियों पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 85.82 करोड़ रुपये की राशि विज्ञापन मद में बकाया दर्शाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन बकायेदार एजेंसियों को गत वर्ष ही बकाया चुकता करने हेतु नोटिस भी जारी की गयी थी लेकिन ऑडिट टीम के जाँच रिपोर्ट में 85 करोड़ की जगह 14 करोड़ का ही खुलासा किया गया और शेष राशि के गबन की आशंका व्यक्त की गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 85 करोड़ की बकाया राशि को रातों रात घटाकर 14 करोड़ करने का क्या औचित्य है और सरकार इसके लिये किसे दोषी मानती है ?

राशन कार्ड दिलाना

*210. श्रीमती पूनम देवी यादव——स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 2 जून, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "राशन कार्ड से वंचित लोगों ने किया जाम" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिले के गौगरी, बेलदौर एवं मानसी प्रखंड में वर्ष 2013 में जिन लोगों को राशन व किरासन तैल के लिये राशन कार्ड दिया गया था, उन लोगों को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

अधिनियम के तहत् बाँटे जा रहे राशन कार्ड से लाभुकों का नाम वंचित कर दिया गया है, जिससे प्रभावित लोग आक्रोशित होकर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राशन कार्ड से वंचित लाभुकों को कबतक राशन कार्ड दिलाने का विचार रखती है ?

जल को आर्सेनिक मुक्त बनाना

*211. डॉ० अच्युतानन्द---दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 28 मई, 2014 के अंक में छपी खबर "मानक से पाँच गुणा अधिक आर्सेनिक पी रहे लोग" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले जैसे वैशाली, समस्तीपुर, सारण, पटना सहित 13 जिलों की जनता मानक से पाँच गुणा ज्यादा आर्सेनिक जल का सेवन करने को विवश है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त जिलों में जल को आर्सेनिक मुक्त बनाने के लिये कौन–से उपायों पर विचार कर रही है और कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*212. श्री ज्ञानचन्द माँझी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत गरखा प्रखण्ड के ग्राम साधपुर में मुख्य सड़क से अनुसूचित जाति बस्ती तक सड़क निकालने के लिये सरकार जमीन अधिग्रहण दो वर्ष पहले किया है और किसानों को जमीन का मुआवजा भी दे दिया है, लेकिन आजतक मापी करके सड़क नही निकाला गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम–साधपुर अनुसूचित जाति बस्ती में मापी करवाकर कबतक सड़क निकालने का काम करेगी और विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेगी, नहीं, तो क्यों ?

हरे राम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा ।

पटना :
दिनांक 03 जुलाई, 2014 (ई०)।

बि०स०मु० (एल०ए०), 35 डी०टी०पी०–450